KRISHI KRANTI 2025 FPO CONCLAVE

WITNESS HISTORY BEING CREATED

February 10, 2025

RCPV Noronha Academy of Administration and Management

Organised by

Supported by

कृषि क्रांति-2025: एफपीओ कॉन्क्लेव का आयोजन 10 फरवरी 2025 को, RCPV प्रशासनिक अकादमी, भोपाल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ,

कृषि क्रान्ति- 2025: FPO कॉन्क्लेव का आयोजन भूमिशा ऑर्गैनिक्स, डिक्की और सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किया गया । इस कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फ़ॉरेन ट्रेड (DGFT) और स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) रहे। अन्य सहयोगी संस्थाओं में जैन इरीगेशन, सोलीडेरीडेड, ANGC, एवं कृषिका नेचुरल्स रहे ।

इस कार्यक्रम में **किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPOs), खरीदार, वित्तीय संस्थान, उद्योग विशेषज्ञ और नीति-निर्माता** शामिल हुए। यह मंच एफपीओ को सशक्त बनाने, कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और बाजार से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ।

उद्घाटन सत्र :

इस कार्यक्रम का शुभारम्भ कैबिनेट मंत्री मंत्री- सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं कैबिनेट मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मंत्री,मध्यप्रदेश शासन द्वारा किया गया ।

APEDA, SBI, DGFT, NCDC, CIMAP, सोलीडेरीडेड, स्टार्टअप इंडिया सेल , कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण और अन्य संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सहकारिता, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग ने कहा कि "2047 में स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को विकसित बनाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। किसानों को तकनीकी अपनाकर अपनी आय और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा।" उन्होंने सहकारिता को समाज का आधार बताते हुए कहा कि "बिना सहकार नहीं उद्धार, बिना संस्कार नहीं सहकार।" जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए उन्होंने डिक्की, भूमिशा ऑर्गेनिक और सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसायटी को सहकारिता विभाग के साथ मिलकर कार्य करने की सलाह दी।

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ने कहा कि "एफपीओ और खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत बनाना किसानों की आत्मनिर्भरता की कुंजी है।" उन्होंने फसल विविधीकरण और कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने घोषणा की कि "राज्य सरकार जल्द ही एक विशाल फूड प्रोसेसिंग सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें किसानों, उद्यमियों, क्रेताओं और विक्रेताओं को एक मंच पर लाया जाएगा।"

इस कार्यक्रम में 150 से ज्यादा FPO प्रतिनिधि एवं 80 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया ।

ज्ञानवर्धक सत्र एवं चर्चाएँ :

- एफपीओ की सस्टेनेबिलिटी और वित्तीय सहायता पर विशेषज्ञों की चर्चा।
- बाजार पहुंच, मूल्य संवर्धन, और पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर मार्गदर्शन।
- सरकारी नीतियों, निर्यात अवसरों और डिजिटल कृषि नवाचारों पर सत्र।

सत्र: **APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority)**

विषय: मध्य प्रदेश के कृषि उत्पादों का निर्यात और वैश्विक बाजार में अवसर

APEDA के बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री अशोक बोरा जी ने किसानों और एफपीओ (FPOs) को निर्यात की संभावनाओं, अंतरराष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं, और गुणवत्ता मानकों पर विस्तृत जानकारी दी। सत्र के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे:

भारत के कृषि निर्यात का परिदृश्य – APEDA के अशोक बोरा जी ने बताया कि भारत दुनिया के कई देशों को अनाज, फल, सब्जियां, प्रोसेस्ड फूड और अन्य कृषि उत्पाद निर्यात करता है। वर्तमान में, जैविक उत्पाद, और मिलेट्स, की मांग बढ़ रही है।

एफपीओ के लिए निर्यात मार्ग – APEDA ने बताया कि एफपीओ को पंजीकरण कराकर निर्यात के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके लिए निर्यात प्रमाणीकरण, गुणवत्ता सुधार, और ब्रांडिंग जैसी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।

वित्तीय सहायता और योजनाएँ – APEDA विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कोल्ड चेन, और वैल्यू एडिशन के लिए सहायता प्रदान करता है। एफपीओ और निर्यातकों को कस्टम क्लियरेंस, पैकेजिंग और लेबलिंग मानकों के बारे में मार्गदर्शन दिया गया।

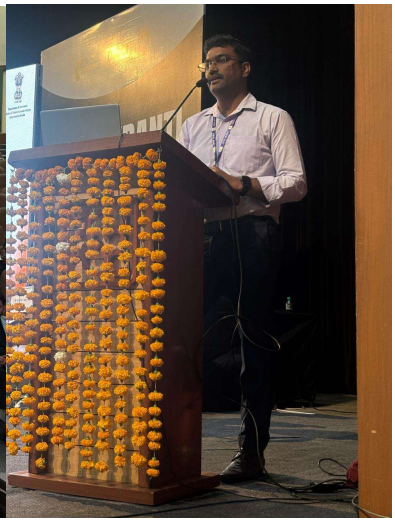

इंटरनेशनल मार्केट एक्सपोजर – APEDA एफपीओ को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों और B2B बैठकों में भाग लेने का अवसर देता है, जिससे वे अपनी उपज को सीधे विदेशी खरीदारों को बेच सकते हैं।

प्रश्नोत्तर सत्र – एफपीओ प्रतिनिधियों ने निर्यात बाधाओं, लाइसेंस प्रक्रिया, और खरीदारों से संपर्क कैसे करें जैसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे, श्री अशोक बोरा जी ने जिनका विस्तार से उत्तर दिया।

सत्र : NCDC (National Cooperative Development Corporation)

विषय: एफपीओ और सहकारी समितियों के लिए वित्तीय सहायता और सशक्तिकरण

NCDC के सत्र में एफपीओ, सहकारी समितियों और किसान संगठनों को वित्तीय सहायता, योजनाएं, और क्लस्टर विकास पर रीजनल डायरेक्टर, NCDC, इन्द्रजीत कौर जी ने चर्चा की । इस सत्र के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे:

NCDC की भूमिका और सहायता योजनाएँ –

NCDC एफपीओ को सीधे ऋण प्रदान करता है, जिससे वे अपनी भंडारण, प्रोसेसिंग, और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं विकसित कर सकते हैं।

सस्ती ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे एफपीओ अपनी बाजार प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकते हैं।

बिजनेस मॉडल और वैल्यू चेन डेवलपमेंट –

सहकारी समितियों और एफपीओ को व्यापारिक रणनीति बनाने और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

उत्पाद प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग के माध्यम से मूल्य संवर्धन पर चर्चा की गई।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सहायता –

गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ, और लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के विकास के लिए आर्थिक सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई।

NCDC संयुक्त निवेश और PPP मॉडल में एफपीओ की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहा है।

सहकारी समितियों के लिए डिजिटल समाधान –

डिजिटल मार्केटिंग, ई-नाम (e-NAM), और को-ऑपरेटिव बैंकिंग पर विशेष चर्चा की गई।

एफपीओ को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और सीधा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए नए मॉडल्स पेश किए गए।

भविष्य की योजनाएँ और सहयोग –

NCDC ने आश्वासन दिया कि वह एफपीओ को निरंतर सहायता प्रदान करेगा और उन्हें बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तकनीकी और वित्तीय मदद देगा।

राज्य स्तरीय एफपीओ क्लस्टर और नेटवर्किंग मीटिंग्स आयोजित करने की योजना बनाई गई।

सत्र: स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI)

विषय: एफपीओ और किसानों के लिए वित्तीय सहायता, ऋण योजनाएँ और बैंकिंग समाधान

SBI की एग्री बिजनेस यूनिट, वरिष्ठ अधिकारी प्रशांत जी ने किसानों और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को कृषि वित्तपोषण, क्रेडिट योजनाओं, और निवेश के अवसरों पर विस्तृत जानकारी दी।

मुख्य बिंदु:

कृषि ऋण योजनाएँ:

प्रशांत जी ने किसानों और एफपीओ के लिए विशेष कृषि ऋण योजनाओं जैसे केसीसी (Kisan Credit Card), एग्री टर्म लोन, और वर्किंग कैपिटल लोन की जानकारी दी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और PM Kisan Samman Nidhi जैसी सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता पर चर्चा की गई।

एफपीओ को बैंकिंग समर्थन:

प्रशांत जी ने एफपीओ के लिए ग्रुप फाइनेंसिंग मॉडल पर चर्चा की, जिसमें सामूहिक गारंटी के आधार पर ऋण सुविधा दी जाती है।

बैंक द्वारा एफपीओ को इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, वेयरहाउस निर्माण और लॉजिस्टिक्स सुधार के लिए सहायता देने की बात कही गई।

डिजिटल बैंकिंग समाधान:

UPI, डिजिटल पेमेंट, और ई-बैंकिंग सेवाओं पर प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसान और एफपीओ डिजिटल लेनदेन को आसानी से अपना सकें।

ई-नाम (e-NAM) और अन्य ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में एफपीओ की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया।

बैंकिंग सुविधाओं पर प्रश्नोत्तर सत्र:

किसानों और एफपीओ ने क्रेडिट लिमिट, ब्याज दर, लोन चुकाने की प्रक्रिया, और सब्सिडी योजनाओं से जुड़े सवाल पूछे, जिनका प्रशांत जी ने विस्तार से उत्तर दिया।

सत्र: जैन इरिगेशन

विषय: माइक्रो-इरिगेशन, आधुनिक कृषि तकनीक और जल प्रबंधन समाधान

जैन इरिगेशन के विशेषज्ञों विवेक डंगरीकर एवं अज़हर जैद जी ने जल संरक्षण, उन्नत सिंचाई तकनीक और कृषि में नवाचार पर गहराई से चर्चा की।

मुख्य बिंदु:

माइक्रो-इरिगेशन तकनीक:

ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम से जल की बचत और उत्पादन वृद्धि पर जोर दिया गया।

किसानों को जल दक्षता बढ़ाने और लागत कम करने के तरीकों की जानकारी दी गई।

स्मार्ट फार्मिंग और सेंसर आधारित इरिगेशन:

डंगरीकर एवं अज़हर जैद जी ने स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम, जिसमें सेंसर आधारित पानी आपूर्ति और ऑटोमैटिक कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं, का प्रदर्शन किया।

मोबाइल ऐप आधारित रिमोट इरिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम को किसानों के लिए उपयोगी बताया गया।

फसल विशिष्ट इरिगेशन समाधान:

फल, सब्जी, अनाज और गन्ना जैसी विभिन्न फसलों के लिए अनुकूलित इरिगेशन मॉडल प्रस्तुत किए गए।

पोलीहाउस और नेट हाउस खेती में ड्रिप इरिगेशन के फायदे बताए गए।

बिजली और उर्वरक बचत समाधान:

सौर ऊर्जा आधारित इरिगेशन पंप और फर्टिगेशन तकनीक पर चर्चा की गई, जिससे किसानों को उर्वरकों की बचत में मदद मिल सकती है।

प्रश्नोत्तर सत्र:

किसानों ने माइक्रो-इरिगेशन सिस्टम की लागत, सब्सिडी योजनाएँ, और रखरखाव प्रक्रियाओं पर सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने समाधान प्रस्तुत किया।

सत्र: सोलिडेरीडैड

विषय: कृषि उत्पादों का सतत उत्पादन और एफपीओ के लिए बाजार संपर्क

सोलिडेरीडैड के जनरल मैनेजर श्री सुरेश मोटवानी ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वैल्यू एडिशन, और एफपीओ को बाजार तक पहुंचाने की रणनीतियों पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्य बिंदु:

सस्टेनेबल फार्मिंग मॉडल:

कम लागत में उच्च उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य सुधार, और जैविक खेती के मॉडल प्रस्तुत किए गए।

मल्टी-क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग तकनीकों पर चर्चा हुई जिससे किसान अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।

एफपीओ के लिए व्यापार और मूल्य संवर्धन:

एफपीओ को वैल्यू चेन डेवलपमेंट, प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप, और मार्केट एक्सपोजर पर मार्गदर्शन दिया गया।

मिलेट्स, ऑर्गेनिक फूड, और स्पेशलिटी एग्रो-प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में प्रमोट करने के तरीके सुझाए गए।

किसानों के लिए वित्तीय सहयोग और सरकारी योजनाएँ:

किसानों और एफपीओ को CSR फंडिंग, सब्सिडी योजनाएँ, और इंटरनेशनल डोनर प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी दी गई।

सुरेश मोटवानी जी ने एफपीओ को सस्टेनेबल ग्रोथ और निर्यात में सहायता देने का आश्वासन दिया।

स्टार्टअप और नवाचार प्रदर्शन:

नए कृषि-तकनीकी स्टार्टअप्स द्वारा उन्नत तकनीकों एवं समाधानों का प्रदर्शन किया गया ।

कृषि रत्न सम्मान एवं सहयोग

कार्यक्रम में 8 एफपीओ और 2 किसानों को '**कृषि रत्न सम्मान**' प्रदान किया गया, जिनका सम्मान पत्र बांस से तैयार किया गया था। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NSDC) द्वारा PMFME योजना के अंतर्गत 2 एफपीओ को 28.5 लाख रुपये की परियोजना स्वीकृत की गई, जिसकी पहली किश्त सहकारिता मंत्री श्री विश्वास सारंग और NSDC की क्षेत्रीय निदेशक इंद्रजीत कौर ने प्रदान की।

बायर-सेलर मीट:

किसानों, एफपीओ और उद्योग जगत के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ।

निर्यातकों, व्यापारियों और प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ संभावित व्यापार समझौते हुए।

बायर-सेलर मीट में निर्यातकों ने फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट, फूड पाउडर, मोरिंगा, जैविक उत्पाद, दालें और चावल की अंतरराष्ट्रीय मांग के बारे में जानकारी दी और एफपीओ को इन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा दी।

'कृषि क्रांति : एफपीओ कॉन्क्लेव' ने किसानों, एफपीओ और एग्री-स्टार्टअप्स के लिए एक नए युग की शुरुआत की है, जहां तकनीक, बाजार और सहकारिता मिलकर कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

विशेषज्ञों के विचार एवं मार्गदर्शन

कॉन्क्लेव में विभिन्न विशेषज्ञों ने भी संबोधित किया, जिनमें सॉलिडरिडाड के जनरल मैनेजर सुरेश मोटवानी, एमपी स्टार्टअप सेंटर के श्री अरुणाभ दुबे, एएनजीसी की डायरेक्टर जयश्री नायर सी-मैप लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. आलोक कृष्णा और उद्यानिकी विभाग के अपर संचालक कमल सिंह किराड़ प्रमुख थे।

कार्यक्रम के प्रमुख निष्कर्ष

बाजार से जुड़ाव और व्यापार अवसर:

कई एफपीओ ने कंपनियों के साथ बाय-बैक समझौते पर चर्चा की।

निर्यातकों के साथ प्रत्यक्ष व्यापार वार्ता से नए अवसर खुले।

वित्तीय एवं नीतिगत सहायता:

एसबीआई एवं अन्य वित्तीय संस्थानों ने एफपीओ को वित्तीय सहायता देने की रुचि दिखाई।

सरकारी योजनाओं, अनुदान और NCDC की सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

एफपीओ और किसानों की क्षमता निर्माण:

वैज्ञानिक खेती, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रोसेसिंग और कृषि मूल्य श्रृंखला पर चर्चा की गई ।

निर्यात तैयारियों और गुणवत्ता मानकों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

भविष्य की रणनीतियाँ और सहयोग:

एफपीओ को लंबी अवधि की सहायता देने के लिए एक फॉलो-अप तंत्र तैयार किया गया।

जिलास्तरीय बायर-सेलर मीट और एफपीओ नेटवर्किंग प्रोग्राम की योजना बनाई गई।

मार्केट लिंकेज से एफपीओ और स्टार्टअप को मिलेगा नया आयाम

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों, एफपीओ और एग्री-स्टार्टअप्स को मार्केट लिंकेज से जोड़ना है। उन्होंने बताया कि यह कॉन्क्लेव कृषि नवाचार, मूल्य संवर्धन और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा।

प्रतिभा तिवारी ,भुमिशा ओर्गानिच्स एवं कृषिका नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड की प्रबंध निदेशक

एफपीओ के विकास में अहम योगदान

डिक्की मध्यप्रदेश में संतरा, मोरिंगा, हल्दी और केसर आम के क्लस्टर बनाकर किसानों को संगठित तरीके से बाजार तक पहुंचने में मदद करेगी। "एफपीओ, एफपीसी, सहकारी संस्थाओं और वित्तीय विभागों को एक मंच पर लाकर कृषि उद्योगों के लिए सुगम मार्ग बनाना आवश्यक है।"

- डॉ. अनिल सिरवैया, अध्यक्ष, डिक्की

कृषि क्रांति-2025 सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि कृषि, तकनीक, बाजार और उद्यमिता को जोड़ने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।" कृषि क्रांति-2025 की यह यात्रा केवल आज तक सीमित नहीं है, बल्कि हम मिलकर इसे एक लंबे और सफल आंदोलन में बदलेंगे। सभी की सहभागिता और समर्थन से हम अपने किसानों को आत्मनिर्भर और कृषि क्षेत्र को और अधिक समृद्ध बना सकेंगे।

- मोनिका जैन, अध्यक्ष, सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसायटी

-

खेती से उद्यमिता तकः एफपीओ के जरिए फूड प्रोसेसिंग में अनेक अवसर

एफपीओ कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन

खेती से उद्यमिता तक-एफपीओ के जरिए फूड प्रोसेसिंग में अनेक अवसर

- एफपीओ कॉन्क्लेव से सहकार की भावना मजबूत होगी
- एफपीओ और खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत बनाना किसानों की आत्मनिर्भरता की कुंजी

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

'कृषि क्रांतिः एफपीओ कॉन्क्लेव' में राज्य सरकार के मंत्रियों, अधिकारियों, विशेषज्ञों, निर्यातकों, क्रेताओं और तकनीकी प्रदाताओं ने एफपीओ के विकास के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य एफपीओ को खाद्य प्रसंस्करण और निर्यात योग्य उत्पाद तैयार करने में सक्षम बनाना था। कॉन्क्लेव का आयोजन भूमिशा ऑर्गेनिक, डिक्की और सर्च एंड रिसर्च डेवपलमेंट सोयायटी ने किया। सहकारिता, खेल एवं युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि 2047 में स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को विकसित बनाने में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। किसानों को तकनीकी अपनाकर अपनी आय और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। उन्होंने सहकारिता को समाज का आधार बताते हुए कहा कि बिना सहकार नहीं उद्धार, बिना संस्कार नहीं सहकार। जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए उन्होंने डिक्की, भूमिशा ऑर्गेनिक और सर्च एंड रिसर्च डेवलपमेंट सोसायटी को सहकारिता विभाग के साथ मिलकर कार्य करने की सलाह दी।

कृषि क्रांति : प्रशासन अकादमी में एफपीओ कॉन्क्लेव का भव्य आयोजन

ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे सॉल्यूशन भी दे रहे युवाओं के स्टार्टअप

सिटी रिपोर्टर| प्रशासन अकादमी में सोमवार को 'कृषि क्रांति : एफपीओ कॉन्क्लेव' का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स, किसानों और बिजनेस ओनर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना था। भूमिशा ऑर्गेनिक, डिक्की और सर्च एंड रिसर्च डेवपलमेंट सोयायटी की ओर से आयोजित कॉन्क्लेव की खास बात यह रही कि यहां एग्रीकल्चर सेक्टर को बदलने वाले स्टार्ट्अप्स देखने को मिले। युवाओं के ऐसे इनोवेटिव आइडिया इस कॉन्क्लेव में सभी को आकर्षित करते नजर आए। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह भी मौजूद रहे।

एग्रीदूत रखता है मिट्टी और फसल की सेहत का ख्याल

करीब 3 साल से एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम कर रहा यह स्टार्टअप 3000 किसानों का असिस्टेंट बना हुआ है। इसके फाउंडर शाश्वत राज और एस राजन ने बताया - एग्रीदूत आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) सेंसर्स और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के जरिए तकनीकी सॉल्यूशन देता है, जिनसे किसानों को कितनी और कौन सी खाद कब डालनी है, सिंचाई कब करनी है या मिट्टी की सेहत कैसी है, इससे जुड़ा अपडेट दे सके।

ड्रोन के जरिए फसलों तक खाद पहुंचाने वाला उद्यम

एग्री बिजनेस डेवलपमेंट कोऑपरेटिव के आदित्य अग्रवाल ने बताया कि हमारी सोसायटी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने के साथ हाईटेक हब भी देती है। इस हाईटेक हब में 10 ड्रोन हैं, जो किसानों की मदद के लिए फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करते हैं। पिछले सीजन में इस हब ने 6000 एकड़ में ड्रोन सर्विस दी। आदित्य बताते हैं कि ऐसे कई नैनो फर्टिलाइजर हैं, जिनका छिड़काव करना ह्यूमन हेल्प से संभव नहीं है, मगर मशीनें चाहें तो इनका छिड़काव कर खेतों को कीड़ों से या खर-पतवार से बचा सकती हैं।

खेती से उद्यमिता तक- एफपीओ के जरिए फूड प्रोसेसिंग में अनेक अवसर